नईदुनिया

भोपाल, 28 नवम्बर 2026

मुख्यमंत्री ने आचार्य विद्यासागर की स्मृति में जारी स्मारक डाक टिकट का किया विमोचन

सच्ची महानता त्याग-तपस्या-परोपकार में



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सच्ची महानता किसी पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और ज्ञान के माध्यम से जीवों के कल्याण में निहित है। महानता अर्जित करने के लिए निःस्वार्थ भाव से सम्पूर्ण जीव-जगत के हित में जीवन समर्पित करना पड़ता है। परमपूज्य संत शिरोमणि 108 आचार्य विद्यासागर महाराज त्याग, संयम, तप और करुणा की प्रतिमूर्ति थे।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को भोपाल के एमपी नगर स्थित विद्योदय तीर्थ में आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति में जारी स्मारक डाक टिकट के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली से आभासी माध्यम से कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज ने गृहस्थ जीवन त्यागकर साधना, भक्ति और जनकल्याण का मार्ग चुना। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को 'जियो और जीने दो' का संदेश दिया। भौतिक रूप से उनके मौजूद न होने के बावजूद उनके विचार और आशीर्वाद आज भी समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं।

समारोह में पांच रुपये मूल्य के स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने संत समय सागर महाराज के सानिध्य में डाक टिकट जारी होने के अवसर पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संत समय सागर महाराज के पाद प्रक्षालन किए और आचार्य विद्यासागर महाराज के चित्र का अनावरण भी किया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत उपस्थित रहे।

एमएसएमई योजनाओं की लंबित राशि जल्द जारी होगी : मांझी



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने नई दिल्ली में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतनराम मांझी से सौजन्य भेंट कर मध्यप्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र में हुए विकास, निवेश और रोजगार वृद्धि की जानकारी दी। उन्होंने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) की लंबित राशि जारी करने का अनुरोध किया।

केंद्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश की उपलब्धियों की सराहना करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। श्री मांझी ने एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने रैम्प योजना और एमएसएमई पंजीयन में बेहतर प्रदर्शन किया है।

मंत्री काश्यप ने बताया कि एमएसई-सीडीपी के तहत स्वीकृत 15 परियोजनाओं में से 10 के केंद्रीय अंश के 7,884.40 लाख रुपये के प्रस्ताव पोर्टल पर भेजे गए हैं, जबकि पांच प्रस्ताव सिडबी में लंबित हैं। रैम्प योजना के तहत 150.51 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके सभी 12 घटकों पर कार्य जारी है। केंद्रीय राशि व्यय के मामले में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर छठे और 100 करोड़ रुपये से अधिक बजट वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है।

काश्यप ने 2,250.50 लाख रुपये की शेष राशि जारी करने, नए प्रस्तावों की स्वीकृति और लंबित मामलों के समयबद्ध निराकरण का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।

दमोह में पारा 6.6 डिग्री पर भोपाल में शीतलहर बरकरार

सुबह कुहासा बना रहने से प्रभावित हो रही दृश्यता

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय न रहने की वजह से मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही शीतल हवाओं के कारण ठंड बरकरार है। इसी क्रम में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात आठ शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।

सबसे कम 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दमोह में रिकार्ड हुआ। भोपाल में लगातार चौथे दिन शीतलहर का प्रभाव रहा। कुहासा बना रहने से शहर में सुबह दृश्याता दो हजार मीटर रही। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। शनिवार को भोपाल, शाजापुर, कटनी, दमोह में शीतलहर का प्रभाव रह सकता है।

सुबह के समय कुहासा रहने से दृश्यता प्रभावित रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में दक्षिणी गुजरात और आसपास के क्षेत्र में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी-मध्य महाराष्ट्र से उत्तरी गुजरात तक एक द्रोणिका बनी हुई है। मौसम विज्ञानी पीके रायकवार ने बताया कि वर्तमान में किसी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय नहीं रहने के कारण मौसम शुष्क ही बना रहेगा। ठंड के तेवर भी इसी तरह बने रहने की संभावना है। वातावरण में बड़े पैमाने पर आर्द्रता मौजूद रहने के कारण राजधानी सहित कई शहरों में सुबह कुहासा रह सकता है। इससे दृश्यता प्रभावित रहेगी। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि अभी तीन-चार दिन तक किसी पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने के आसार नहीं हैं। इस वजह से अभी तीन दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है।

7 से 11 दिसंबर तक आयोजित होगा कर्मयोगी राज्य सीखें सप्ताह

नप्र, भोपाल : मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत द्वितीय कर्मयोगी आईगॉट राज्य सीखें सप्ताह का आयोजन 7 से 11 दिसंबर तक किया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक विभाग और जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में आईगॉट मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष तीन लोकसेवकों को भी सम्मानित किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने विभाग प्रमुखों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों से आयोजन की समयबद्ध तैयारी तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की बेहतर रैंकिंग हासिल करना है।

सप्ताह के दौरान प्रत्येक शासकीय अधिकारी और कर्मचारी को आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप पर न्यूनतम तीन घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना होगा। इसमें दो सामान्य पाठ्यक्रम और एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल होगा।

उमा भारती ने टिकट वाले बयान पर दी सफाई

बोलीं- अहंकार नहीं, सच्चाई है

- उमा ने कहा- पार्टी ने हर बार चुनाव लड़ने के लिए राजी किया
- मोहन सरकार के कामकाज से भी जताई संतुष्टि



नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपालः लोकसभा चुनाव 2029 में टिकट मिलने को लेकर दिए बयान पर राजनीतिक चर्चा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई दी।

उन्होंने कहा कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत के दौरान कही गई बात अहंकार नहीं, बल्कि सच्चाई थी। पार्टी ने उन्हें कभी टिकट नहीं दिया, बल्कि हर बार चुनाव लड़ने के लिए राजी किया है। दो दिन पहले ग्वालियर स्टेशन पर पत्रकारों ने उनसे आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर सवाल किया था। इस पर उन्होंने कहा था कि टिकट देने की किसकी औकात है, वह खुद तय करती हैं कि चुनाव लड़ना है या नहीं। बयान सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थीं।

उमा भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेता सामान्य परिवारों से निकलकर राष्ट्रीय सेवा के जरिए जनता और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पहचान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी जिम्मेदारी मिलने में व्यक्ति, उसकी जरूरत और योगदान देने की क्षमता अहम होती है। इन आधारों पर जनता और संगठन के कार्यकर्ता व्यक्ति को स्वीकार करते हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कामकाज पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री का सहयोग करना चाहिए। शराब नीति पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की नीति को बेहतरीन बताया और हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सांसद और सीएमओ के अपर सचिव में तकरार

'राजनीति करनी है तो चुनाव लड़ें'

- मरकाम ने पूछा- मंडला का मेडिकल कॉलेज अब तक क्यों अटका?

नप्र, भोपाल : मंडला के विकास और मेडिकल कॉलेज परियोजना को लेकर भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम के बीच विवाद सामने आया है। गुरुवार को डिंडौरी दौरे पर पहुंचे सांसद कुलस्ते ने मरकाम के बयानों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार को बदनाम करने और जनता को भड़काने वाले अधिकारी नहीं चाहिए। यदि राजनीति करनी है तो चुनाव लड़कर जनता के बीच जाएं।

विवाद की शुरुआत बुधवार को हुई, जब अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम मंडला के दौरे पर पहुंचे थे। युवाओं और ग्रामीणों से संवाद के दौरान उन्होंने जिले के विकास को लेकर सवाल उठाए। मरकाम ने कहा कि मंडला में विकास की संभावनाएं थीं, लेकिन उनका पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और पॉलीटेक्निक संस्थान की कमी का मुद्दा भी उठाया। मरकाम ने शहडोल, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज होने का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि मंडला में अब तक मेडिकल कॉलेज परियोजना क्यों अटकी हुई है। उन्होंने बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन पिछड़े जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, उनमें मंडला भी शामिल था।

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को विधि विभाग में पदेन सचिव घोषित किया

नप्र, भोपाल : सामान्य प्रशासन विभाग ने उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की नई जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं। राजेश कुमार यादव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश को विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग में पदेन उप सचिव तथा वीरेन्द्र सिंह को पदेन अवर सचिव घोषित किया गया है।

आंगनबाड़ी भर्ती में डिजिटल नवाचार, 22 हजार से अधिक नियुक्तियां

नप्र, भोपाल : आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से पारदर्शी और सरल बनाया गया है। आयुक्त, महिला एवं बाल विकास संदीप जीआर ने बताया कि चयन पोर्टल के माध्यम से अब तक 22 हजार पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। विज्ञापन से नियुक्ति तक पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने 20 नवंबर 2024 को चयन पोर्टल का शुभारंभ किया था। तीन चरणों में कुल 26,819 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जिनमें 4,381 कार्यकर्ता और 22,438 सहायिकाओं के पद शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्यमी संवाद में उद्योगों के विस्तार, सुविधाओं और निवेश को लेकर की चर्चा

जबलपुर से देवास होते हुए इंदौर-उज्जैन तक विकसित होगा औद्योगिक कॉरिडोर



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जबलपुर से देवास होते हुए इंदौर और उज्जैन तक औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इससे देवास में उद्योगों के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता संबंधी समस्या दूर करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को देवास में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देवास में औद्योगिक विकास की संभावनाएं व्यापक हैं। यहां बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। देवास के समीप देश का पहला डीप टेक रिसर्च पार्क विकसित हो रहा है, जिससे उद्योगों को आधुनिक तकनीक और अनुसंधान का लाभ मिलेगा। औद्योगिक पार्कों में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के प्रावधान किए जा रहे हैं। इससे होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और श्रमिकों के आवास विकसित हो सकेंगे। बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

देवास के महाप्रबंधक उद्योग निलंबित, पर्यवेक्षक की वेतन वृद्धि रोकी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान आवेदकों की समस्याएं सुनीं और लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। शिकायतों के निराकरण में उदासीनता और संबंधित प्रकरण की नस्ती प्रस्तुत नहीं करने पर महाप्रबंधक उद्योग रतन सिंह डावर को निलंबित करने के निर्देश दिए। लाड़ली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संबंधित पर्यवेक्षक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। सैनिक स्व. पवन यादव के परिवार को 10 लाख रुपये सहायता देने की घोषणा करते हुए उनके शहीद दर्जे पर विचार करने की बात कही। वन अधिकार पट्टाधारी किसान लाल सिंह को फसल बीमा राशि नहीं मिलने पर 50 हजार रुपये सहायता देने की घोषणा की गई। वहीं, नल जल योजना संबंधी शिकायत पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एक लाख रुपये की पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए।

उद्योगों की समस्याओं पर दिए निर्देश

उद्यमियों ने भूमि, पानी, आधारभूत सुविधाओं, बैंक ऋण और उद्योगों के लिए अनुमतियों की प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं एवं सुझाव रखे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। उद्योगों में एनिमल फीड की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने के सुझाव पर भी उन्होंने गंभीरता से जांच और कार्रवाई करने को कहा।

अनिल माहेश्वरी द्वारा भूमि आवंटन संबंधी समस्याएं उठाने पर मुख्यमंत्री ने जिला उद्योग अधिकारी को एक सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई कर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

होम-स्टे, पशुपालन और स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में होम-स्टे, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को मजबूत बनाने के लिए दूरगामी योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक व्यवसाय अपनाएं, लेकिन खेती की जड़ों को न भूलें। कृषि समृद्धि और संस्कृति का आधार है। उन्होंने योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने और विकास कार्यों की विधानसभा व वार्ड स्तर पर निगरानी करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को कौशल विकास, आधुनिक तकनीक और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा उद्यमियों को ई-कॉमर्स और डिजिटल माध्यमों से बाजार तक पहुंच बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव डॉ. सुदाम खाड़े, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी उपस्थित रहे।

किफायती दरों पर जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता

- कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में 96.45 प्रतिशत तक की कमी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कैंसर रोगियों को उपचार में आर्थिक राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दवाओं की कीमतों में कमी की गई है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में दवाओं की कीमतों में कमी मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। नवोदय कैंसर अस्पताल में शुक्रवार को मध्यप्रदेश राज्य मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (एमपी पीएमआरयू) ने जन-जागरूकता एवं औषधि मूल्य निगरानी अभियान चलाया। अभियान में 300 से अधिक मरीजों, परिजनों, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्टों को संशोधित दवा कीमतों तथा उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी दी गई।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के 1,364 फॉर्मुलेशन्स पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत निर्धारित किया है। 9 नवंबर से लागू प्रावधानों के तहत संबंधित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 96.45 प्रतिशत तक कमी आई है।

दवा खरीदने से पहले कीमत जांचें

नागरिक 'फार्मा सही दाम' एप अथवा एनपीपीए की वेबसाइट से दवाओं के निर्धारित मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने दवा खरीदते समय पक्का बिल लेने और निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूले जाने पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। एमपी पीएमआरयू ने अस्पताल की फार्मेसी का ऑडिट कर चयनित दवाओं की कीमतों और संशोधित एमआरपी की जांच भी की। चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्टों को दवा मूल्य संबंधी प्रावधानों से अवगत कराया गया।

मावलंकर की जयंती पर किया नमन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि संसदीय परंपराओं की स्थापना, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा और सार्वजनिक जीवन में मावलंकर के आदर्श सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे।

अजय सिंह सीईसी ज्ञानेश कुमार के साथ फोटो को लेकर विवाद में घिरे

बोले- मुझे नहीं पता था कि फोटो में मौजूद व्यक्ति ज्ञानेश कुमार हैं, भाजपा ने कसा तंज



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुरहट विधायक अजय सिंह (राहुल) मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ फोटो को लेकर विवाद में घिर गए हैं। दोनों की तस्वीर 23 नवंबर को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) के डीजी उपेंद्र जैन के बेटे के विवाह समारोह में खिंची थी।

अजय सिंह ने यह तस्वीर स्वयं सोशल मीडिया पर साझा की थी। जब मीडिया ने उनसे कांग्रेस द्वारा ज्ञानेश कुमार का विरोध किए जाने के बावजूद उनके साथ फोटो खिंचवाने को लेकर सवाल किया, तो अजय सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि तस्वीर में मौजूद व्यक्ति ज्ञानेश कुमार हैं। उन्होंने बताया कि समारोह में उपेंद्र जैन, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। किसी ने उनका परिचय नहीं कराया और फोटो खींच ली गई।

अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है और उनके पद छोड़ने के बाद ही उनसे बातचीत का सवाल उठेगा। तस्वीर सामने आने के बाद भाजपा ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि अजय सिंह नर्सरी के बच्चे नहीं हैं, जो किसी से डर जाएं।

पुनर्वास *केन-बेतवा सहित चार परियोजनाओं में मुआवजा और पुनर्वास संबंधी शिकायतों पर प्रमुख सचिव को दिए निर्देश...*

सिंचाई परियोजनाओं की शिकायत पर सिलावट ने मांगी जांच रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल। केन-बेतवा लिंक परियोजना सहित छतरपुर और पन्ना जिले की मझगायां, रूंझ और नेगुवा सिंचाई परियोजनाओं में मुआवजा, पुनर्वास और कथित अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने संज्ञान लिया है। उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर 15 दिनों के भीतर जांच कर बिंदुवार प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जय किसान संगठन के प्रमुख अमित भटनागर ने 12 नवंबर को पूर्व सांसद वृंदा करात और दिव्या अहिरवार के साथ भोपाल में मंत्री को ज्ञापन सौंपा था। इसमें प्रभावित किसानों और आदिवासी परिवारों की समस्याओं, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा निर्धारण तथा पुनर्वास प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई थी।

मंत्री ने 16 नवंबर को प्रमुख सचिव को पत्र जारी कर ज्ञापन के बिंदुओं पर जांच कराने के निर्देश दिए थे। यह पत्र 27 नवंबर को डाक के माध्यम से अमित भटनागर को प्राप्त हुआ।

ज्ञापन में वर्ष 2026 को कट-ऑफ डेट निर्धारित करने, सिंचित भूमि का उचित मुआवजा देने, वन स्वीकृति की शर्तों का पालन कराने, पूर्ण मुआवजा और पुनर्वास से पहले विस्थापन रोकने तथा चारों परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई थी।

अमित भटनागर ने कहा कि संगठन विकास के विरोध में नहीं, बल्कि किसानों, आदिवासियों और विस्थापित परिवारों के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच के बाद प्रभावित परिवारों को न्याय मिलेगा।

पकड़े 41 हजार बिजली चोरी के प्रकरण, 70 करोड़ वसूले

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने चालू वर्ष में बिजली चोरी और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 41 हजार से अधिक प्रकरण पकड़े हैं। एक जनवरी से अब तक 98 हजार से अधिक स्थानों पर जांच की गई। इन मामलों में 93 करोड़ रुपये की बिलिंग की गई, जबकि अब तक 70 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल की जा चुकी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देशानुसार बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनी लगातार अभियान चला रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि इंदौर और उज्जैन क्षेत्र के सभी 15 जिलों में सतर्कता दल और संबंधित टीमों द्वारा जांच की जा रही है। तकनीकी संकेतों, प्राप्त सूचनाओं और मौके पर गड़बड़ी मिलने के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। नियमित जांच के अलावा विशेष दल गठित कर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी एसआर बमनके ने बताया कि पिछले पांच महीनों में एप पर 520 सूचनाएं मिलीं, जिनके आधार पर करीब 88 लाख रुपये की बिलिंग की गई। सही सूचना देने वालों को सीधे लाभ अंतरण प्रक्रिया के माध्यम से पुरस्कार भी दिया जा रहा है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com